

पेरिस समझौते के नौ वर्ष

प्रलम्बिस के लयि:

पेरिस समझौता, UNFCCC, राषटरीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC), कयोटो प्रोटोकॉल बनाम पेरिस समझौता, जलवायु वतित, साझा लेकनि वभिदति ज़मिमेदारियॉ (CBDR), वशिव मौसम वजिज्ञान संगठन (WMO) रपिरट, अंतरराषटरीय नयायालय (ICJ), लघु दवीपीय वकिसशील राजय (SIDS)

मेन्स के लयि:

पेरिस समझौते की उपलब्धियॉ और चुनौतियॉ, वैश्वकि जलवायु वतित संबन्धी मुद्दे और उनका नवारण

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यॉ?

12 दसिंबर, 2015 को अंगीकृत [पेरिस समझौते](#) के नौ वर्ष पूरण होने के साथ इसकी संवीकषा की जा रही है ।

- वैश्वकि तापमान वृद्धि को सीमति करने के अपने महत्तवाकांक्षी लक्ष्यो के बावजूद, हालिया रुझान [जलवायु परविरतन](#) का शमन करने में इसकी [प्रभावहीनता](#) को उजागर करते हैं । पछिले नौ वर्षो में, वैश्वकि उत्सर्जन में 8% की वृद्धि हुई है और अनुमानतः वर्ष 2024 में पहली बार यह [पूर्व-औद्योगकि स्तरों](#) से ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से अधिक हो जाएगा ।

पेरिस समझौता क्या है?

परचिय:

- यह [जलवायु परविरतन पर संयुक्त राषटर फरेमवरक कनवेंशन \(UNFCCC\)](#) के तहत वधिकि रूप से बाध्यकारी वैश्वकि समझौता है जिसका अंगीकार वर्ष 2015 (COP 21) में कया गया था ।
- इसका उद्देश्य तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमति रखने की महत्तवाकांक्षा के साथ [जलवायु परविरतन का शमन करना](#) और वैश्वकि तापमान को पूर्व-औद्योगकि स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमति रखना है ।
- इसने [कयोटो प्रोटोकॉल](#) का स्थान लया जो जलवायु परविरतन के शमन हेतु एक पूर्व समझौता था ।
- पेरिस समझौते के अंतर्गत, प्रत्येक देश को हर पाँच वर्ष में अपने [राषटरीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(NDC\)](#) प्रस्तुत करना और उसे अद्यतन करना होता है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परविरतन के अनुकूल होने की उनकी योजनाओं की रूपरेखा होती है ।
 - NDC, देशों द्वारा अपने [ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने](#) तथा जलवायु परविरतन के प्रभावों के अनुकूल कार्य करने हेतु की गई प्रतजिजाएँ हैं ।

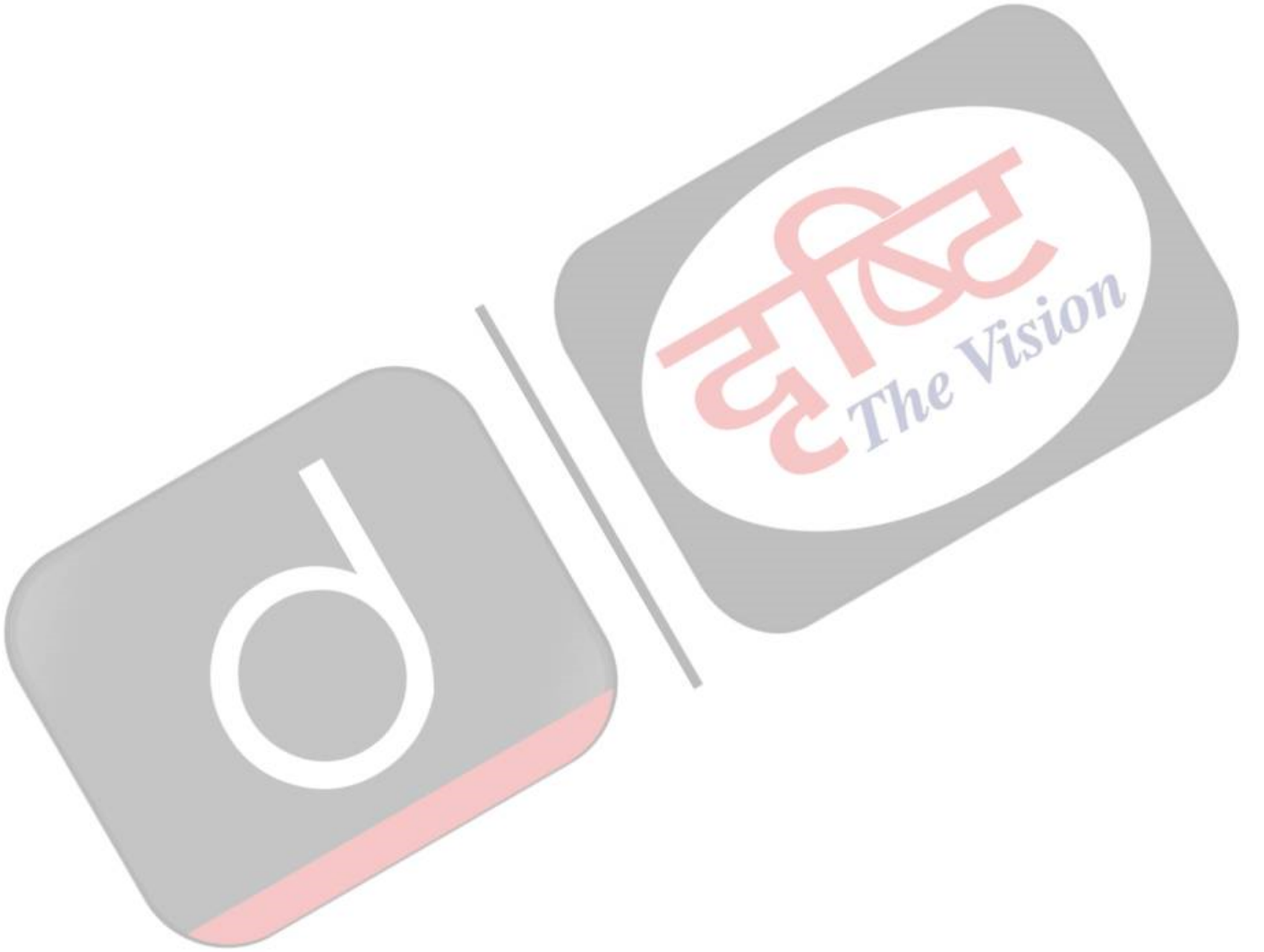
उपलब्धियॉ:

- [वैश्वकि सहमति और समावेशिता](#): ऐसा प्रथमतः है जब, लगभग सभी राषटर, [वकिसति](#), वकिसशील और अल्प वकिसति, एक सार्वभौमकि ढाँचे के तहत जलवायु परविरतन से निपटने के लयि प्रतबिद्ध हैं, जहाँ सभी देश [राषटरीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(NDC\)](#) के माध्यम से योगदान करते हैं, जिससे वैश्वकि भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चति होती है ।
- [वकिसशील देशों के लयि वतिततीय सहायता](#): वकिसति देशों ने [वकिसशील देशों को शमन और अनुकूलन](#) में सहायता देने के लयि 2020 तक प्रतविरष 100 बलियिन अमेरिकी डॉलर जुटाने का संकल्प लया है, जिसमें कमज़ोर देशों के लयि सतत् वकिस को सक्षम बनाने के लयि वर्ष 2020 के बाद वतिततीय प्रतबिद्धताओं को बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है ।
- [समानता और वभिदति ज़मिमेदारियॉ](#): राषटरीय परस्थितियॉ के आधार पर प्रतबिद्धताओं को संतुलति करने के लयि "[साझा लेकनि वभिदति ज़मिमेदारियॉ \(CBDR\)](#)" के UNFCCC सिद्धांत को शामिल कया गया, जिससे वकिसशील और अल्प वकिसति देशों के लयि नषिक्षता सुनिश्चति हुई ।

- [आलोचना](#): वशिव [वशिव मौसम वजिज्ञान संगठन \(WMO\)](#) की वर्ष 2022 की [स्टेट ऑफ द ग्लोबल कलाइमेट](#) रपिरट के अनुसार [जलवायु परविरतन पर पेरिस समझौता](#) अपने एजेंडे को पूरा करने में अप्रभावी रहा है ।

- समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, पछिले आठ वर्ष (2015-2022) लगातार वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष रहे हैं।
 - यदि पछिले तीन वर्षों में **ला नीना मौसम घटना** नहीं घटी होती, तो स्थिति और भी संकटपूर्ण हो सकती थी, जिसका मौसम प्रणाली पर शीतलन प्रभाव पड़ता है।
- वर्तमान **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)** परतबिद्धताएँ वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिये अपर्याप्त हैं, जिसमें 2.5-2.9 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है तथा लक्ष्यों एवं वास्तविक कार्यान्वयन के बीच अंतर के कारण वर्ष **2030 तक उत्सर्जन और भी अधिक हो सकता है।**
- विश्व **मौसम वजिज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट** में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2015 का पेरिस समझौता पर्याप्त नहीं है तथा इसके पूरक के रूप में जीवाश्म ईंधन संधि की आवश्यकता है।
- यद्यपि कई देशों में एनडीसी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ लागू हैं, फिर भी उनकी पर्याप्तता एवं कार्यान्वयन प्रभावशीलता अलग-अलग हैं।
 - उदाहरण के लिये, जबकि यूरोपीय संघ के एनडीसी **यूरोपीय ग्रीन डील की तरह सुदृढ़ लक्ष्य और कार्यान्वयन को दर्शाते हैं**, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश कोयले पर निर्भरता तथा सीमित संसाधनों के कारण **प्रभावी कार्यान्वयन के लिये संघर्ष करते हैं।**

//





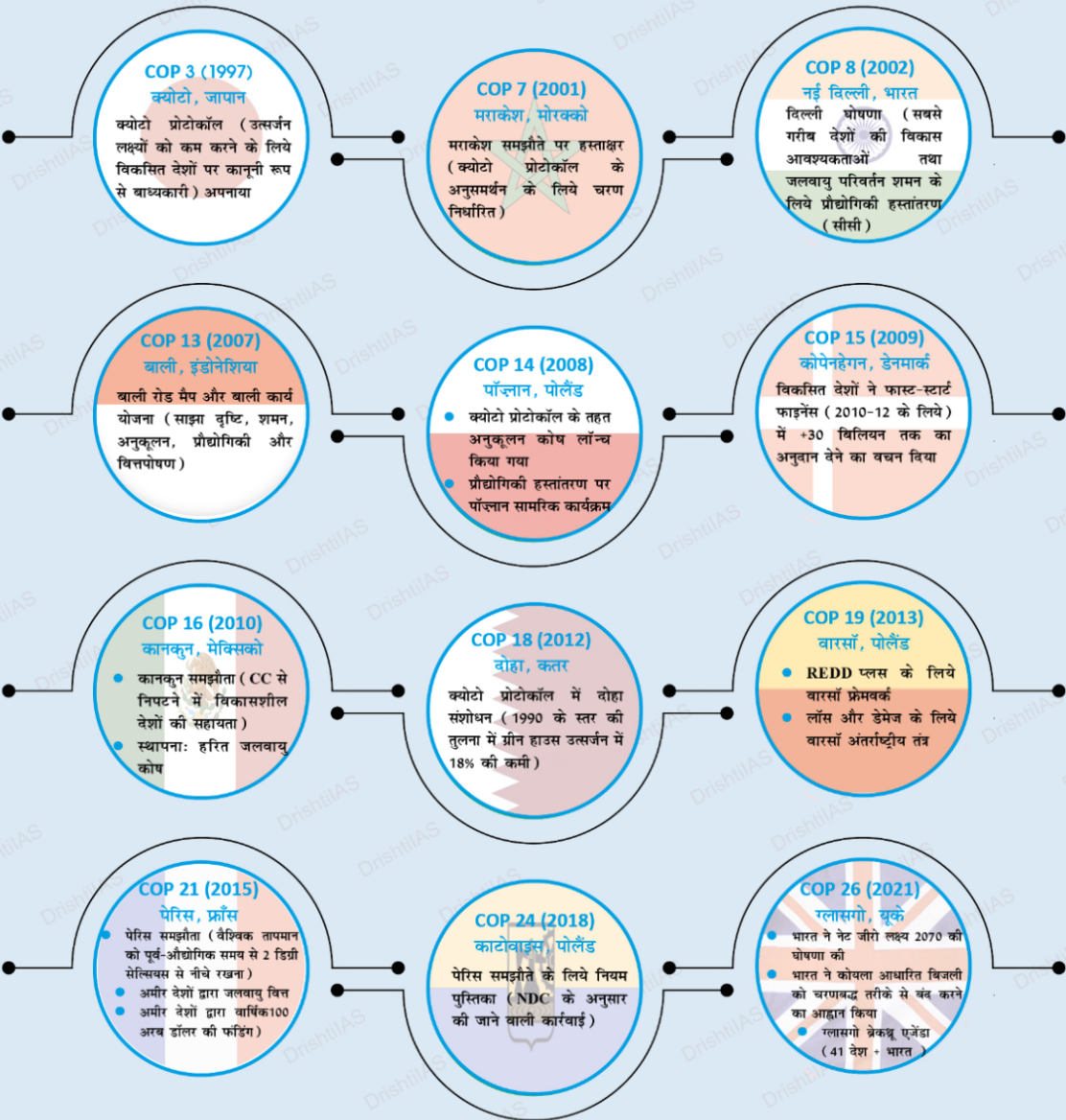
UNFCCC

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)

कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज:

- UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था
- प्रत्येक वर्ष बैठक होती है (जब तक कि पक्षकार अन्यथा निर्णय न लें)
- बॉन, सचिवालय में बैठक (जब तक कि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती)
- पहला सीओपी- बर्लिन, जर्मनी में आयोजित (1995)

COPs और उनके प्रमुख परिणाम



COP 27 (2022)

शर्म-अल-शेख, मिस्र

- लॉस और डेमेज फंड
- पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिये USD 3.1 बिलियन की योजना

- जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों के लिये G7 के नेतृत्व वाली 'ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी'
- अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल
- जल अनुकूलन और लचीलापन (AWARe) पहल के लिये कार्रवाई
- मैग्नेट एलायंस (भारत के साथ साझेदारी में)
- भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति





पेरिस समझौते पर वकिसति, वकिसशील और अल्पवकिसति देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण क्या हैं?

पहलू	वकिसति देश	वकिसशील देश	अल्प-वकिसति देश (LDCs)
एनडीसी के प्रति दृष्टिकोण	लचीलेपन के लिये स्वैच्छक एनडीसी का पक्ष लें।	स्वैच्छक एनडीसी की अपर्याप्त एवं असमान बताते हुए आलोचना करना।	मज़बूत वैश्विक कार्रवाई के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की मांग करना।
जलवायु वित्त	कम औद्योगिकीकृत देशों पर अधिक ज़िम्मेदारी डालने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।	वकिसति देशों से पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सहायता का समर्थन करना।	वादा किये गए वित्तपोषण में विलंब और अपर्याप्तता से निराशा, विशेष रूप से अनुकूलन और हानि एवं क्षति के लिये।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	सीमति, बाज़ार-आधारित प्रौद्योगिकी साझाकरण का समर्थन करना।	हरति अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिये सुलभ एवं कफ़ायती प्रौद्योगिकी की मांग करना।	महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की कमी पर प्रकाश डालना, जिससे उनकी भेद्यता वृद्धि होती है।
ऐतहासिक ज़िम्मेदारी	ऐतहासिक उत्सर्जन जवाबदेही से आगे बढ़ने का प्रयास करना।	वकिसति देशों को जवाबदेह ठहराने के लिये "साझा लेकिन वभिदति ज़िम्मेदारियों" (CBDR) के सिद्धांत पर परचिरचा करना।	वैश्विक कार्रवाई में नषिपक्षता सुनिश्चित करने के लिये ऐतहासिक उत्सर्जन को संबोधित करने के महत्त्व पर ज़ोर देना।
अनुकूलन हेतु आवश्यकताएँ	अनुकूलन की अपेक्षा शमन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना।	वर्तमान और भविष्य के जलवायु प्रभावों से नषिटने के लिये शमन एवं अनुकूलन दोनों पर ज़ोर देना।	गंभीर कमज़ोरियों, विशेषकर समुद्र-स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं के कारण अनुकूलन को प्राथमिकता देना।
लॉस एंड डैमेज	मुआवज़ा या क्षतिपूरति देने में अनच्छिछा प्रदर्शति करना।	हानि और क्षति से नषिटने के लिये मज़बूत तंत्र की स्थापना का समर्थन करना।	उनके असततित्व को संकट में डालने वाले अपरवित्तीय जलवायु प्रभावों के लिये तत्काल कार्रवाई और क्षतिपूरति की मांग करना।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिये क्या कया जा सकता है?

- **एनडीसी को सुदृढ़ और लागू करना:** एनडीसी को तापमान लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिये समय-समय पर समीक्षा के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि वकिसति देश अपने ऐतहासिक उत्सर्जन एवं वित्तीय क्षमता को दर्शाते हुए स्वच्छ शमन लक्ष्य को अपनाएँ।
- **जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना:** जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये एक बाध्यकारी वैश्विक ढाँचा स्थापित करना, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिये वकिसशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा नवियों को प्राथमिकता देने के लिये जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करना।
- **जलवायु वित्त को बढ़ावा देना:** वकिसति देशों को वर्ष 2035 तक 300 बलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य को पार करना होगा, कमज़ोर देशों के लिये अनुकूलन और लॉस एंड डैमेज वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना होगा तथा कार्बन कर एवं वमिानन कर जैसे

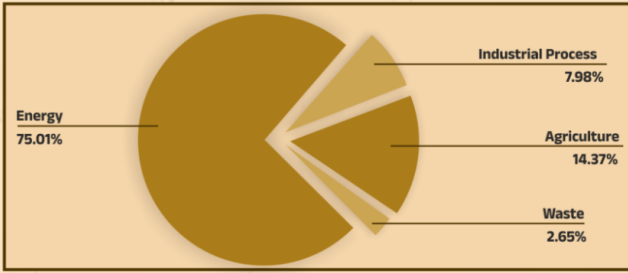
नवीन तंत्रों को लागू करना होगा।

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना:** कफायती प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से तकनीकी क्षमता का निर्माण करना तथा टिकाऊ नवाचार एवं परिनियोजन के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **अनुकूलन और जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति विकसित करना, लचीले बुनियादी ढाँचे में निवेश करना तथा जलवायु-प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- **न्यायसंगत कार्यान्वयन और जवाबदेहिता: सीबीडीआर को बहाल करके** समानता को बनाए रखना, एनडीसी और वित्त के लिये पारदर्शी जवाबदेहिता स्थापित करना तथा गैर-अनुपालन के लिये दंड के साथ अनुपालन के लिये प्रोत्साहन को लागू करना।
- **वैश्विक सहयोग में वृद्धि:** बाकू में COP29 के हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर, **एकीकृत वैश्विक कार्रवाई** को सुविधाजनक बनाने के लिये **बहुपक्षीय संस्थाओं को मज़बूत करने** और गैर-अनुपालन के लिये जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाले मज़बूत वैश्विक ढाँचे की स्थापना की आवश्यकता है।

भारत की जलवायु परिच्छेदिका/प्रोफाइल

क्षेत्रवार योगदान

- ⊕ **प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र:** ऊर्जा, परिवहन, निर्माण



- ⊕ **प्रमुख जलवायु जोखिम:** बाढ़, सूखा, हीटवेव, कोल्डवेव और चक्रवात
- ⊕ **कमज़ोर क्षेत्र:** कृषि और खाद्य, जल, तटीय, स्वास्थ्य, वन और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रमुख पहल

- ⊕ **राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा**
 - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
 - जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)
- ⊕ **भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (वर्ष 2022)**
 - 'जीवन' के लिये जन आंदोलन - 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली'
 - आर्थिक विकास हेतु जलवायु-अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना
 - वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
 - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता
 - 2.5 से 3 बिलियन टन CO₂ का अतिरिक्त कार्बन सिंक
 - विशिष्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से अपनाना
 - घरेलू और नई एवं अतिरिक्त निधियाँ एकत्रित करना

- क्षमताओं का निर्माण करना, घरेलू ढाँचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना
- ⊕ **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता - UNFCCC (1994) कन्वेंशन और समझौते**
 - पेरिस समझौता (2015)
 - क्योटो प्रोटोकॉल (2005)

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग

द्विपक्षीय परियोजनाएँ

- ⊕ **ड्यूश गोसेलशाफ्टफ्यूर इंटरनेशनल ज़ुसामेनरबीट (GIZ) GmbH (जर्मनी)**
 - ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त (CAFRI) (वर्ष 2020-2023)
 - राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई (NAMAs) (वर्ष 2007)
 - ग्लोबल कार्बन मार्केट (GCM) (वर्ष 1997)
 - जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्रवाई पर क्षमताओं का संस्थागतकरण (ICCC)
- ⊕ **यूरोपीय संघ (EU)**
 - पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये रणनीतिक साझेदारी (SPIPA) (वर्ष 2018-2022)
 - इको-सिटीज़ के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ और ऊर्जा दक्षता

बहुपक्षीय परियोजनाएँ

- ⊕ **संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (वर्ष 2019)**
- ⊕ **अनुकूलन पर वैश्विक आयोग (GCA) (2018)**
- ⊕ **UNDP:** राज्य-स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बाज़ार परिवर्तन और बाधाओं को दूर करना



Drishti IAS

प्रश्न: पेरिस समझौते की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये और इसके कार्यान्वयन में चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न 1. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइ० पी० सी० सी०) ने वैश्विक समुद्र-स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग एक मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। यदि महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा? (2023)

प्रश्न 2. ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिये और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिये नयितरण उपायों को समझाइये। (2022)

प्रश्न 3. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nine-years-of-the-paris-agreement>

